to be examined further before we can say that a large quantity of high grade coal is there.

ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्योग

\+

* 359. **श्री म० ल० द्विवेदी :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गुलशन :

क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना के बारे में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये सुझाव क्रियान्वित करने के लिये भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) भूतकाल में ग्रामीण क्षेत्रों में इन उद्योगों की स्थापना में धीमी गति के क्या कारण हैं; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में इन उद्योगों के विस्तार के लिये मंत्रालय द्वारा बनाई गई योजना की मुख्य बातें क्या हैं तथा इसको किस रूप में क्रियान्वित किया जायेगा ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० सिंह) : (क) से (ग). सदन की मेज पर एक विवरण रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 3541/64].**

श्री म० ल० द्विवेदी : अध्यक्ष महोदय, पहले मैं आप की सूचना में यह बात लाना चाहता हूं कि इस विवरण में लिखा गया है :

"The broad features of this scheme are given in the annexure."

लेकिन उत्तर के साथ एनेक्शर नहीं दिया गया है, जिस के कारण पूरी जानकारी नहीं मिल सकी है ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि देश में देहातों की संख्या 85 प्रतिशत होते हुए भी सरकार का ध्यान देहाती इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ़ बहुत कम गया है और उस की प्राग्रेस बहुत स्लो है, जो कि मिनिस्टर महोदय स्वयं भी स्वीकार करते हैं।

श्री त्रि० न० सिंह : यह बात नहीं है कि सरकार का ध्यान इस तरफ़ नहीं है । हमारे देश में जब से स्वराज्य आया है, तब से सरकार ने बराबर इसपर जोर दिया है । जहां तक प्राग्रेस के स्लो होने का सम्बन्ध है, असली बात यह है कि यह मसला बड़ा टेढ़ा और पेचीदा है । इस सम्बन्ध में कई तरीके किये गये हैं, लेकिन जिसको पूरी सफलता कहते हैं, वह नहीं मिली है, यह ठीक बात है ।

श्री म० ल० द्विवेदी : इस बयान में इंडस्ट्री की तरक्की न होने के कई कारणों में एक कारण यह भी बताया गया है :

"Lack of local entrepreneurship apart from the required infra-structure such as power suitable skill, communications and transport facilities etc."

मैं यह जानना चाहता हूं कि इन सुविधाओं को मुहैया करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है और कब तक ये सुविधायें देहाती क्षेत्रों में उपलब्ध हो सकेंगी, ताकि उद्योग चालू हो सकें ।

श्री त्रि० न० सिंह : यह काम बड़े विस्तार का है । पांच, साढ़े पांच लाख गांवों में बिजली पहुंचाना कोई मामूली बात नहीं है । तीसरी योजना में करीब साठ हजार गांवों में बिजली पहुंचाने की कोशिश की जा रही है । आगे चल कर चौथी योजना

में एक लाख गांवों में बिजली पहुंच जायेगी। हमारा ख्याल है कि जब बड़े बड़े गांवों में बिजली पहुंच जायेगी, तो वहां पर बिजली के द्वारा बहुत से उद्योग खड़े हो सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने जो एनेक्शर न मिलने के बारे में कहा है, मिनिस्टर साहब उस को भी देख लें।

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं इस का पता लगाऊंगा।

Shrimati Savitri Nigam: It has been mentioned in the statement that it is agreed that these programmes have not resulted in rural industrialisation to any sufficient extent. In view of the fact that all the steps taken by Government so far have not made any impact on rural industrialisation, what are the new schemes, proposals and steps taken by Government to see that the capacity of these rural areas to fulfil the schemes already sanctioned and are going to be sanctioned is increased? Also are Government going to provide cheap loans to people in the rural areas for the purpose?

Mr. Speaker: If there are more than one question joined in one question, the Minister might answer only one, whichever he chooses.

Shri T. N Singh: We have begun efforts regarding rural industries only towards the end of the Second Plan. It is true that projects regarding cluster centres have not made that progress which was expected. As I said earlier, the problem is very intricate and we are trying to feel our way through a method which would really make a breakthrough in this matter.

Shri S. C. Samanta: How much new employment per year has been created through the 45 rural industries projects that are run at present?

Shri T. N. Singh: These projects are in the very beginning stages. Therefore, it is not possible to give those figures.

श्री ओंकार लाल बेरवा : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस योजना में राजस्थान को कितना रुपया दिया गया है और क्या वह सारा खर्च कर दिया गया है ; यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रि० ना० सिंह : जहां तक मुझे ख्याल है, अभी तक उसमें रुपया खर्च नहीं हुआ है, लेकिन पूरी रकम के बारे में ज्यादा तफ़सील देने के लिए मैं नोटिस चाहूंगा।

श्री शिव नारायण : अंग्रेज के जमाने में तो हमारे अंगूठे काट दिये जाते थे, ताकि हमारे देश का इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट न हो, लेकिन आज इस सरकार के रास्ते में गांवों का इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट करने के लिए क्या रुकावट है ? (*Interruption*). गांवों के किसानों ने इस गवर्नमेंट को वोट दिया है। मिनिस्टर एक्सप्लेन करें कि इसमें क्या दिक्कतें हैं ?

श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या माननीय सदस्य को कल का गुस्सा है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं हर एक मेम्बर से विनती करूंगा कि वह दलील के साथ गवर्नमेंट की नुक्ताचीनी बेशक करें, लेकिन गुस्से में न आयें।

श्री शिव नारायण : कम से कम वह बतायें कि इसमें दिक्कतें क्या हैं।

श्री त्रि० ना० सिंह : हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने 1963 में एक कांफ्रेंस में बोलते हुए कहा था कि गांवों में बिजली पहुंचाना बहुत जरूरी है। मैं उनकी इस राय से पूरा इत्तिफ़ाक करता हूं। जब यह काम हो जायेगा, तभी गावों में लघु-उद्योगों का प्रचार हो सकेगा।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिन हजारों गांवों में अभी तक बिजली गई है, उनमें से कितने परसेंटेज गांवों में लघु-उद्योगों की स्थापना हो सकी है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : इस प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि बिजली के अलावा और भी कई चीजों की जरूरत होती है । एन्टरप्रेनर्ज होने चाहिएं, जो कि पूंजी लगा सकें और इंडस्ट्रीज को चला सकें, इस विषय की स्किल होनी चाहिए, ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए । इंडस्ट्रीज लगाने के लिए ऐसी बहुत सी चीजों की जरूरत होती है और वे ऐसी चीजें हैं, जिनमें समय लगेगा ।

श्री यशपाल सिंह : क्या यह सही है कि खादी कमिशन ने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह नहीं निभाया है, इस लिए देहात अनडेवेलप्ड रह गए हैं ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मेरी मिनिस्ट्री का खादी कमीशन से ताल्लुक नहीं है । मैं माननीय सदस्य से दरख्वास्त करूंगा कि वह सम्बद्ध मिनिस्ट्री से यह सवाल पूछें ।

Shri Ranga: Have Government any inspectorate to go round the country and make either a comprehensive or a sample survey of the manner in which the funds granted by the Union Government to the Khadi and Village Industries Commission and various other commissions that have started small scale corporations and so on are being put to proper use?

Shri T. N. Singh: As I said earlier, the Khadi Commission is the concern of another Ministry. What other commission is he referring to?

Shri Ranga: My hon. friend happened to be chairman of the Public Accounts Committee and he came to know of so many discrepancies. Although Parliament has created all these corporations and given them some semi-autonomous or autonomous powers, I would like to know whether Government are taking any steps to see that the funds placed at their disposal are being put to proper use?

Shri T. N. Singh: I again plead that the hon. Member, as an experienced parliamentarian, knows the subjects which are my concern. The Khadi Commission and other commissions to which he is referring are not within my Ministry, and therefore, it will not be possible for me to answer those questions.

Shri Ranga: But who else is taking those steps?

श्री रामेश्वरानन्द : देहात में जो लघु उद्योगों का यत्न किया जा रहा है वह किस प्रकार से किया जा रहा है, किन के द्वारा आपकी जो इच्छा है वह देहातों तक पहुंचती है ? कौन लोग हैं या कौन सा विभाग है जो देहात वालों को कहता है कि लघु उद्योग लगाओ ?

श्री त्रि० ना० सिंह : हमारे अफसर हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अफसर हैं और बहुत से जनता के बड़े बड़े पुराने कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हैं ।

श्री रामेश्वरानन्द : कौन से अफसर हैं कौन से विभाग हैं जो जनता को यह कहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि विभाग कौन सा है जो जनता को यह खबर पहुंचाता है कि आपकी यह इच्छा है कि देहाती लोग छोटे छोटे उद्योग लगायें ?

श्री त्रि० ना० सिंह : आपकी हिदायत है कि मैं इसका जवाब दूं ?

अध्यक्ष महोदय : जब मैंने दोहरा दिया है तो इजाजत की क्या जरूरत है ?

स्वामी जी मैं क्या कर सकता हूं अगर वह जवाब न दें तो ।

Shri S. N. Chaturvedi: May I know how these new 45 projects that are mentioned in the statement are functioning, and the difference in their approach to the problem from the others that were taken up earlier?

Shri T. N. Singh: This is a new kind of programme started in 1962 when we had called a conference of all the State Industries Officers and others. There it was decided that it is desirable to have an integrated

development programme which would be intimately connected—not only an exclusive industrial programme—with the agricultural and other development programmes in these areas.

श्री काशीराम गुप्त : खादी ग्रामोद्योग कमिशन गांवों में कपड़े के उत्पादन के बारे में सफल नहीं रहा है और जहां जहां बिजली पहुंच गई है वहां वहां इसकी सफलता के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस विषय में सोचा गया है कि ऐसी छोटी छोटी मशीनें कताई और बुनाई की, बिजली से चलने वाली लगाई जायें जहां जहां बिजली पहुंच गई है ताकि इस कपड़े के मामले में सफलता प्राप्त हो सके ?

श्री त्रि० ना० सिंह : खादी और ग्रामोद्योग के सम्बन्ध में जानकारी दूसरा मंत्रालय ही दे सकता है । लेकिन जहां तक नई मशीनें बहुत सी बनाने की बात है, उसके लिए स्माल स्केल इंडस्ट्रीज का जो टैक्नीकल विंग है, वह इस क्षेत्र में बहुत से काम कर रहा है ।

Shri K. N. Pande: Is it not a fact that the Patel Committee, which was appointed by the Planning Commission, has recommended the establishment of small-scale industries in Eastern U.P.? May I know the developments in this connection?

Shri T. N. Singh: It is true that the Patel Committee has prepared a blueprint for these four districts in East U.P., and they are being implemented as and when possible.

श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या यह बात सही है कि केन्द्र द्वारा राज्यों को जो पैसा लोन देने के लिए दिया जाता है, उस पैसे को लेने के लिए जनता को काफी कठिनाइयां होती हैं और काफी परेशानी उठाने के बाद ही लोगों को लोन मिल पाता है और बहुत से केसिस में दिया भी नहीं जाता है ? क्या यह भी सही है कि बिजली पाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और अगर मिलती भी है तो वह बहुत विलम्ब से मिलती है ? क्या इस बारे में सरकार की ओर से कुछ किया गया है या राज्यों को आदेश दिये गये हैं कि व लोगों की कठिनाइयों को हल करें और जो विलम्ब होता है उसको दूर करें ?

श्री त्रि० ना० सिंह : कभी कभी कठिनाइयों की बात सामने आई है और समय समय पर बराबर हम लोगों ने अपनी तरफ से कायदे और तरीके बदलने की कोशिश की है और स्टेट गवर्नमेंट्स से अक्सर इस बारे में बातचीत हुआ करती है ।

श्री तुलशीदास जाधव : समाजवादी समाज स्थापित करने की पालिसी गवर्नमेंट की चूंकि है, इसलिए प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्ज आगे नहीं आते हैं, दूसरे आपकी मशीनरी जो है वह लोगों के पास जाकर उनको धंधे स्थापित करने के लिए नहीं कहती है और तीसरे गांव वाले खुद भी निकालते नहीं हैं, क्या यह बात सही है यदि नहीं तो इन तीनों कारणों में से कौन सा कारण है जिसकी वजह से धंधे निकलते नहीं हैं और किस तरह से आप समझते हैं कि धंधे निकल सकेंगे ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि समाजवाद का हमारा उद्देश्य होने की वजह से इस काम में कोई रुकावट पड़ रही है । मैं समझता हूं कि बराबर इन पिछले वर्षों में सामंजस्य रहा है और इस काम में काफी उन्नति हुई है ।

Shri Dinen Bhattacharya: May I know whether the handloom industry is included in this rural industrialisation scheme and, if so, what steps are the Government taking to supply adequate yarn to the handloom weavers especially in West Bengal where the weavers are suffering owing to the dearth of adequate supply of yarn?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah): Yes, Sir. Handloom is included in this and a public

sector mill in Kalyani has been set up. Another mill is being set up for the West Bengal handloom weavers for the supply of yarn to handlooms.

Production and Price of Mill Cloth

+

*360. **Shri Prakash Vir Shastri:**
Shri Shree Narayan Das:
Shri Jagdev Singh Siddhanti:
Shri Vishram Prasad:
Shri Bagri:
Shri Bibhuti Mishra:
Shri K. N. Tiwary:
Shri P. C. Borooah:
Shri Ram Sewak Yadav:
Shri P. R. Chakraverti:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Gulshan:
Shrimati Renuka Ray:
Shri Y. S. Chaudhary:
Shri B. K. Das:
Shri Dinen Bhattacharya:
Dr. Ranen Sen:
Dr. Saradish Roy:
Shrimati Jyotsna Chanda:

Will the Minister of **Commerce** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 129 on the 11th September, 1964 and state:

(a) the effective date on which statutory controls were introduced on the production and prices of popular varieties of mill cloth;

(b) whether the control has proved effective; and

(c) the organisational set up for exercising supervision over the working of the control?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah): (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-3542/64).

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : प्राय: देखा गया है कि सरकार जिन जिन चीज़ों का नियन्त्रण करती हैं वे वे चीजें बाजार से गायब हो जाती हैं। कपड़े के ऊपर भी जब नियन्त्रण किया जा रहा है, तो अच्छी किस्म का कपड़ा बाजार से गायब न हो जाए, इसके लिए भी कोई व्यवस्था कर दी गई है ?

श्री मनुभाई शाह : इतना कपड़ा आज बाजार में मुहैया है होलसेल में और रिटेल में और मिलों में भी और उसके अलावा उत्पादन हैंडलूम सैक्टर का तथा पावरलूम सैक्टर का और मिलों का भी इतना बढ़ रहा है कि जो चिन्ता माननीय सदस्य ने व्यक्त की है, उसका कोई कारण नहीं है :

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या इसका भी आपने यत्न किया है कि अच्छा कपड़ा जिसका आपने नियन्त्रण किया है, इसके जो मूल्य हैं, उन्हीं मूल्यों पर बाजार में यह मिल सके, अधिक मूल्यों पर न मिले ? क्या इसकी देख रेख की भी कोई व्यवस्था आपने की है ?

श्री मनुभाई शाह : स्टटमेंट को अगर देखा जाए तो उसमें कहा गया है कि पूरी व्यवस्था, व्यापक व्यवस्था राज्य लेवल पर जिले के लेबल पर और गाव के लेबल पर कर दी गई है।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती: मन्त्री महोदय ने फरमाया कि बहुत कपड़ा बन रहा है। लेकिन गांव के लोग जो कपड़ा पहनते हैं, उनके उपयोग का जो कपड़ा है, जैसे धोती है, पगड़ी का पकड़ा है, कुर्ते का कपड़ा है ....

एक माननीय सदस्य : लंगोटी है।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : उन सब कपड़ों के दाम आपके कथनानुसार आसमान पर चढ़े हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इन कपड़ों के दामों को कम करने का यत्न भी क्या आपकी तरफ से होगा ?

श्री मनुभाई शाह : इसी कपड़े को कण्ट्रोल में लाया गया है।

श्री बागड़ी : मिलों में तैयार होने वाले कपड़े के दाम क्या उसी नीति पर तय किये गये हैं जिस नीति पर कि खाद्य पदार्थों के दाम जो किसान पैदा करता है, तय किये गये हैं ? क्या